



2026:AHC:124688-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 9526/2026

राजजन लाल श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता

तर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

ण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: अंशुल कुमार गुप्ता, हनुमान प्रसाद कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद कुशवाहा और श्री इंद्रजीत सिंह तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिकाएँ निम्नलिखित राहतों के साथ दायर की गई हैं:-

"1. दिनांक 07.04.2026 को दर्ज की गई एफआईआर, मुकदमा अपराध संख्या 382/2026, के रूप में धारा 316(5) बीएनएस, 2023 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ललितपुर, जिला ललितपुर को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश (अनुलग्नक संख्या 1) ।

II. मुकदमा अपराध संख्या 382/2026, धारा 316(5) बीएनएस, 2023 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश (अनुलग्नक संख्या 1)।"

3. वर्तमान प्रकरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

4. एफआईआर में मौजूद मुख्य आरोप राजजन लाल श्रीवास्तव और राघवेंद्र सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह चौहान दोनों के खिलाफ हैं। जबकि पहले वाले गोदाम प्रभारी हैं और दूसरे कैडर सचिव हैं, दोनों याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का यह कहना है कि 2070.96 क्विंटल गेहूं के गबन का मुख्य आरोप दूसरे के कदाचार के कारण है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता राघवेंद्र सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह चौहान के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राजन लाल श्रीवास्तव भंडार प्रभारी थे। उन्होंने गेहूं की मात्रा का गबन किया था और विभागीय कार्यवाही के दौरान उन्होंने कमी की गई राशि जमा करने का वचन दिया था। राघवेंद्र सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह चौहान को कैडर सचिव बताते हुए, जिन्होंने भंडार या खरीद केंद्र के प्रकरणों के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने सारा दोष राजन लाल श्रीवास्तव पर डाल दिया है।

5. राजन लाल श्रीवास्तव के विद्वान अधिवक्ता ने समान रूप से यह तर्क दिया कि पूरी घटना राघवेंद्र सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह चौहान के कारण हुई थी। वे अपने प्रकरण के समर्थन में एफआईआर में दर्ज आरोपों पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, वे भी अपनी निर्दोषता का दावा करते हैं। इसके अलावा, केवल इसलिए कि राजन लाल श्रीवास्तव ने दिनांक 12.06.2025 को रिट-ए संख्या 6822/2025 में पारित आदेश में दर्ज राशि का भुगतान करने का वचन दिया था, इससे उस आपराधिक दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके कारण वर्तमान मुकदमा चल रहा है। यदि एक ही लेन-देन से दो परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं - एक दीवानी और दूसरा आपराधिक - तो आपराधिक अपराध की कार्यवाही अपने आप में मान्य होगी।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ तथ्यात्मक आरोप मौजूद हैं। चूंकि लगभग 2071 क्विंटल गेहूं के गबन के मूल तथ्यात्मक आरोप पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी कीमत 55 लाख रुपये है, और जांच अभी भी जारी है, इसलिए ऐसे तथ्यों में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, जहां तक याचिकाकर्ताओं को रिट याचिकाओं में आरोपी व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, इस बात से मामले के गुण-दोष पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापी यादव को एफआईआर प्रपत्र में संबंधित कॉलम के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, क्योंकि एफआईआर में घटना के विस्तृत विवरण में उनका नाम शामिल है।

8. अन्य आरोपी राजजन लाल श्रीवास्तव की ओर से उठाई गई आपत्तियों के संबंध में, तथ्यात्मक आरोप मौजूद हैं। इस प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ताओं की निर्दोषता या अपराध के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकारी योजना के तहत प्राप्त गेहूं की बड़ी मात्रा के गबन के तथ्यात्मक आरोप मौजूद हैं। इस तथ्य का कोई प्रभावी खंडन नहीं है। व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका और उन पर लगाए जा सकने वाले आरोपों की सीमा के संबंध में अन्य सभी तथ्यों पर जांच पूरी होने के बाद टिप्पणी की जा सकती है।

9. तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मांगी गई हस्तक्षेप याचिका अस्वीकृत की जाती है।

10. याचिकाकर्ताओं को विधि के अनुसार वैधानिक उपचारों का लाभ उठाने की छूट देते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

2 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह) (माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)